

आयकर आयुक्त, दिल्ली एवं राजस्थान

बनाम

मैसर्स नेशनल फाइनेंस लिमिटेड

29<sup>th</sup> January, 1962

(न्यायमूर्ति एस.के. दास, एम. हिदायतुल्ला और जे.सी. शाह)

आयकर-पूंजीगत हानि या ट्रेडिंग हानि- स्पेयर्स में डीलर- कंपनी की एजेंसी प्राप्त करने के लिए शेयरों का अधिग्रहण- बाद में नुकसान उठाने वाले शेयरों की बिक्री-चाहे ट्रेडिंग हानि हो- ट्रिब्यूनल में आवेदन समय\_सीमा वर्जित के रूप में खारिज कर दिया गया-उच्च न्यायालय में रिफरेंस खारिज-अपील अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति द्वारा-धारणीयता।

प्रतिवादी शेयरों और प्रतिभूतियों में काम करने वाली एक कंपनी थी और सभी एक ही व्यक्ति द्वारा नियंत्रित कंपनियों के समूह से संबंधित थी। मूल्यांकन वर्ष 1951-52 के अनुरूप लेखा वर्ष में, प्रतिवादी ने मधुसूदन मिल्स लिमिटेड से संबंधित शेयर बेच दिए, जिसे उसने कुछ समय पहले हासिल किया था, जिससे उसे घाटा हुआ, जिसके लिए उसने लाभ के विरुद्ध समायोजन का दावा किया। आयकर अधिकारी ने पाया कि विचाराधीन शेयर समूह से संबंधित कंपनी जे द्वारा उस कीमत पर खरीदे गए थे जो मौजूदा बाजार मूल्य से लगभग दोगुना था, ऐसा विक्रेताओं को उनके पद से हटाने के उद्देश्य से किया गया था। प्रबंध एजेंसी और प्रतिवादी के लिए मिल्स की क्रय और विक्रय एजेंसी सुनिश्चित करना, और खरीद के बाद जे ने अपने नियंत्रित हित को ध्यान में रखते हुए उद्देश्य हासिल किया और मिल्स की क्रय और विक्रय एजेंसी प्रतिवादी को दे दी गई, हालांकि बाद वाला जे को ऋण देने के अलावा और कुछ नहीं किया था। यह भी पाया गया कि खरीद के तुरंत बाद संबंधित शेयर प्रतिवादी के कब्जे में आ गए और जब शेयर बेचे गए तो वे बाजार में नहीं थे बल्कि दूसरे को नुकसान हो रहा था। एक ही समूह से संबंधित कंपनी. आयकर अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शेयर प्राप्त करने में प्रतिवादी ने उनके साथ स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में व्यवहार नहीं किया, बल्कि एक स्थायी प्रकृति की पूंजीगत संपत्ति प्राप्त कर रहा था। तदनुसार, उन्होंने घाटे को पूंजीगत हानि मानते हुए दावे को अस्वीकार कर दिया। हालांकि, अपीलीय न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी के पक्ष में यह विचार रखा कि प्रतिवादी कंपनी और जे के बीच अंतर किया जाना चाहिए।

आयकर आयुक्त ने उच्च न्यायालय के संदर्भ के लिए ट्रिब्यूनल का रुख किया, लेकिन इसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि हालांकि इस पर केवल एक दिन की रोक लगाई गई थी और आयुक्त की ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई थी, ट्रिब्यूनल ने समय बढ़ाने की शक्ति नहीं है। उच्च न्यायालय में दायर एक

आवेदन भी खारिज कर दिया गया। आयकर आयुक्त इसके बाद कर के लिए आवेदन किया गया और ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति मिल गई। जब अपील तय

866

SUPREME COURT REPORTS

[1962] SUPP.

समय पर सुनवाई के लिए आई तो प्रतिवादी ने आपत्ति जताई कि अपील सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई थी, और चंडी प्रसाद चोकानी बनाम बिहार राज्य के फैसले पर भरोसा किया, ( 1962) 2 एस.सी.आर. 276.

*माना गया* कि अपील विचार योग्य थी क्योंकि उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार करने का कोई सवाल ही नहीं था, जो केवल सीमा के प्रश्न पर ट्रिब्यूनल के निर्णय की शुद्धता से संबंधित था जो वर्तमान अपील का विषय नहीं था।

आगे, *माना गया* कि ऐसी विशेष परिस्थितियाँ थीं जो विशेष अनुमति देने को उचित ठहराती थीं। बलदेव सिंह बनाम आयकर आयुक्त (1960), 40 1.टी.आर. 605, लागू किया गया।

यह भी माना गया कि, तथ्यों पर, उद्देश्य लाभदायक चरित्र की कुछ एजेंसियों का अधिग्रहण करने के लिए बाजार मूल्य से कहीं अधिक कीमत पर शेयरों का एक बड़ा ब्लॉक खरीदना था, कि जे द्वारा शेयरों की खरीद केवल एक उपकरण थी लेकिन नियंत्रित हित प्रतिवादी द्वारा अर्जित किया गया था, और लेन-देन को पूंजी में से एक माना जाना चाहिए।

*रामनारायण संस (पी.) लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, (1961) 2 एस.सी.आर. 904 और ओरिएंटल इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, (1958) एस.सी.आर. 49, लागू किया गया।*

*सॉलोमन बनाम सॉलोमन एंड कंपनी लिमिटेड (1897) ए.सी. 22, डिस्टिन देखा गया ।*

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1960 की सिविल अपील संख्या 559।

आईटीए क्रमांक 2070 का 1956-57 में भारतीय आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (दिल्ली बेंच) के 1/14 मई, 1957 के फैसले और आदेश से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

के.एन. अपीलकर्ता की ओर से राजगोपाल शास्त्री और डी. गुप्ता।

29 जनवरी 1962 न्यायालय का फैसला सुनाया गया

हिदायतुल्ला, जे.- यह आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, दिल्ली बेंच, दिनांक 1/14 मई, 1957 के आदेश के खिलाफ एक अपील है, जिसके द्वारा न्यायाधिकरण ने अपीलीय सहायक आयुक्त के आदेश को पलटते हुए कहा था कि प्रतिवादी कंपनी द्वारा कुछ शेयरों की बिक्री से होने वाली हानि पूंजीगत हानि थी। यहां दिए गए ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद, आयकर आयुक्त, नई दिल्ली, जो हमारे समक्ष अपीलकर्ता हैं, ने आदेश से उत्पन्न होने वाले कानून के कुछ प्रश्नों पर उच्च न्यायालय के संदर्भ के लिए ट्रिब्यूनल को स्थानांतरित कर दिया था। अपीलीय न्यायाधिकरण के उस आवेदन को एक दिन की अवधि से समय बाधित पाया गया, और चूंकि, कानून के तहत, ट्रिब्यूनल के पास समय बढ़ाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, इसलिए आवेदन खारिज कर दिया गया था। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ आयकर अधिनियम की धारा 66(3); के तहत हाई कोर्ट में अर्जी दायर की गई थी। लेकिन उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल से सहमत होकर आवेदन खारिज कर दिया कि संदर्भ के लिए ट्रिब्यूनल का आवेदन समय से बाधित था। तब आयकर आयुक्त ने ट्रिब्यूनल द्वारा उसके समक्ष अपील में पारित आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति के लिए आवेदन किया था, और विशेष अनुमति के साथ वर्तमान अपील दायर की गई है।

इससे पहले कि हम मामले की गुण-दोष की जांच करें, हम प्रतिवादी की ओर से उठाए गए प्रारंभिक आपत्ति से निपटेंगे कि अपील चंडी प्रसाद चोखानी बनाम बिहार राज्य (1) में इस न्यायालय के फैसले के मद्देनजर आय-पेटेंट है। जहां यह माना गया कि यह न्यायालय बहुत ही असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, उच्च न्यायालय के फैसले को नजर अंदाज करते हुए ट्रिब्यूनल के आदेश से सीधे अपील पर विचार नहीं करेगा। अपीलकर्ता बलदेव सिंह बनाम आयकर आयुक्त (2) में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करता है और तर्क देता है कि बाद वाले मामले में विद्यमान और पूर्व में विज्ञापित असाधारण परिस्थितियाँ वर्तमान मामले को नियंत्रित करती हैं।

प्रासंगिक तारीखों के साथ संदर्भ के लिए आवेदन दाखिल करने से संबंधित तथ्य ये हैं: ट्रिब्यूनल का आदेश दो विद्वान सदस्यों द्वारा पारित किया गया था, जिन्होंने अलग-अलग तारीखों पर अपने संबंधित आदेशों पर हस्ताक्षर किए थे। लेखाकार सदस्य ने 1 मई, 1957 को और न्यायिक सदस्य ने 14 मई, 1957 को अपने आदेश पर हस्ताक्षर किये। आदेश की सूचना आयकर आयुक्त, नई दिल्ली को भेजी गई और 15 जुलाई, 1957 को पंजीकृत डाक से उनके कार्यालय में पहुंची। इसे आयकर आयुक्त के कार्यालय में एक clerk मोतीलाल पाठक ने प्राप्त किया। मोतीलाल के हलफनामे से पता चलता है कि वह अचानक बीमार पड़ गए और उन्हें एक दिन की आकस्मिक छुट्टी लेनी पड़ी। वह अगले दिन कार्यालय लौटा, और ट्रिब्यूनल से प्राप्त नोटिस का निपटारा किया। एक गलती से, जिसे समझना आसान है, कागजात की प्राप्ति की तारीख की मोहर 16 तारीख को चिपकाई गई थी, और उस तारीख को वास्तविक तारीख के बजाय, यानी 15 तारीख को अंकित किया गया था, जिस दिन कागजात वास्तव में थे प्राप्त हुआ। तारीख की मोहर पर भरोसा करते हुए, सभी ने यह मान लिया कि 16 जुलाई, 1957 से गिनती करते हुए सीमा 60 वें दिन समाप्त हो जाएगी। आवेदन उस अनुमान पर सीमा के अंतिम दिन दायर किया गया था। दरअसल, आवेदन पर एक दिन की रोक लगा दी गई थी। इसलिए, आयकर न्यायाधिकरण ने 4 दिसंबर, 1957 को आवेदन खारिज कर दिया। न्यायाधिकरण के फैसले को उच्च न्यायालय के समक्ष असफल रूप से चुनौती दी गई। यह स्पष्ट है कि ट्रिब्यूनल का निर्णय बिल्कुल सही था, और ट्रिब्यूनल के पास आवेदन को खारिज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि कानून ट्रिब्यूनल को सीमा बढ़ाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं देता है, जैसा कि धारा 5 भारतीय सीमा अधिनियम के तहत किया जाता है।

इस अदालत ने अपील में पारित ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति दी ।

इससे पहले, और सवाल यह है कि क्या चोखानी के मामले (1) में फैसले के मद्देनजर अपील पर सुनवाई की जानी चाहिए या अनुमति रद्द कर दी जानी चाहिए। चोखानी के मामले (1) में, निर्णय के लिए न्यायालय के निर्णय को दरकिनार करने का प्रयास किया गया था और उच्च न्यायालय का एक अन्य निर्णय भी था कि ट्रिब्यूनल के आदेश से कानून का कोई अन्य बिंदु उत्पन्न नहीं हुआ था, यह माना गया था कि यह न्यायालय उच्च न्यायालय को नजर अंदाज करने की अनुमति नहीं देगा और परिस्थितियों में ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील करना अक्षम था। इसी तरह का विचार फिर से दो अन्य मामलों में व्यक्त किया गया था, अर्थात्, इंडियन एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त (2) और कन्हैयालाल लोहिया बनाम आयकर आयुक्त (3)। तीनों मामलों में, अपीलकर्ताओं द्वारा ढाकेसवारी कॉटन मिल्स, लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त (4) और बलदेव सिंह बनाम आयकर आयुक्त (5) में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया गया था। इस न्यायालय के निर्णयों में यह बताया गया था कि जिन दो मामलों पर भरोसा किया गया था उनका निर्णय वहां मौजूद विशेष परिस्थितियों पर किया गया था। पहले में, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का प्रश्न था, जिसे इस न्यायालय की विशेष अनुमति के साथ अपील के अलावा अन्यथा नहीं उठाया जा सकता था। दूसरे मामले में, यह बताया गया कि पार्टी ने बिना किसी गलती के सीमा बाधित हो गयी, यहां तक कि एक पत्र को पोस्ट करने में अनावश्यक देरी हुई। हमारी राय में, वर्तमान मामले में भी, विशेष परिस्थितियाँ मौजूद हैं जो बलदेव सिंह के मामले (5) में विशेष अनुमति देने को उचित ठहराती हैं। परिस्थितियों का एक संयोजन था जिसके कारण आवेदन एक दिन की देरी से दाखिल किया गया, लेकिन परिस्थितियों से पता चला कि चूक आयकर आयुक्त की ओर से किसी भी लापरवाही के कारण नहीं थी। 15 जुलाई को नोटिस की प्राप्ति स्वीकार की जाती है; लेकिन 16 तारीख की मोहर लगाने एवं 15 तारीख को नोटिस का निपटान में विफलता क्लर्क के बीमार पड जाने और कार्यालय छोड़ने के कारण हुआ ।

यह सामान्य ज्ञान है कि कार्यालय में हर दिन तारीख टिकटें बदली जाती हैं, और यह काम ज्यादातर बहुत कनिष्ठ कर्मचारी द्वारा किया जाता है। 16 तारीख की तारीख की मोहर लगाने और उसके परिणामस्वरूप उस तारीख वाले नोटिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, और तारीख की मोहर पर भरोसा करते हुए, अपील दायर की गई, हालांकि परिसीमा के आखिरी दिन लेकिन समय के भीतर। इन परिस्थितियों में, यह कहना मुश्किल है कि आयकर अधिकारी लापरवाह था और यदि क्लर्क की ओर से गलत तारीख का टिकट लगाने में लापरवाही, यदि कोई हो, तो वह क्षम्य है यदि उसकी 15 तारीख को बीमारी से छुट्टी एवं अनुपस्थिति पर विचार किया जाये। हमारी राय में, यह मामला बलदेव सिंह के मामले <sup>(1)</sup> के नियम के अंतर्गत आता है और ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ सीधे इस न्यायालय में अपील विशेष परिस्थितियों में उचित है। इस अपील के द्वारा, उच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय को दरकिनार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उच्च न्यायालय का निर्णय परिसीमा के प्रश्न पर ट्रिब्यूनल के निर्णय की शुद्धता से संबंधित है, जो कि ऐसा प्रश्न नहीं है जिसकी मांग वर्तमान अपील द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से की जा रही है। इसलिए, हम प्रारंभिक आपत्ति को खारिज करते हैं।

निर्धारिती कंपनी नेशनल फाइनेंस लिमिटेड, नई दिल्ली है। यह एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जिसे 1943 में स्थापित किया गया था। यह शेयरों और प्रतिभूतियों के साथ-साथ फाइनेंसरों के रूप में भी काम करती है। वर्तमान मामला निर्धारिती कंपनी द्वारा मधुसूदन मिल्स लिमिटेड, बॉम्बे के 3,000 शेयरों के सौदे से उत्पन्न हुआ है। लेखा वर्ष में, 1 मई 1949 से 30 अप्रैल 1950, आकलन वर्ष 1951-52 के अनुरूप, कंपनी ने इन शेयरों को 5,48,712 8.0/- रुपये का नुकसान सहते हुए बेच दिया। जिसका उसने अपने स्टॉक-इन-ट्रेड की बिक्री पर दावा किया था। आयकर अधिकारी और अपीलिय सहायक आयुक्त ने इसे पूंजीगत स्टॉक माना।

अपीलीय न्यायाधिकरण, दिल्ली बेंच ने निर्णय को पलट दिया और निर्धारिती कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया। इस अपील में एकमात्र सवाल यह है कि क्या ट्रिब्यूनल का निर्णय सही है।

निर्धारिती कंपनी लाला योध राज भल्ला और उनसे जुड़े कुछ व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित कंपनियों के समूह से संबंधित है। इन व्यक्तियों को 'योध राज भल्ला समूह' के रूप में वर्णित करना सुविधाजनक है। ये कंपनियाँ हैं (1) जसवन्त शुगर मिल्स लिमिटेड, (2) जसवन्त स्ट्रॉ बोर्ड्स लिमिटेड, (3) नेशनल फाइनेंस लिमिटेड, (4) नेशनल कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (5) गणेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और (6) रघुनाथ इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड। इन कंपनियों का अंतर्संबंध बहुत घनिष्ठ है, और वे व्यावहारिक रूप से 'योध राज भल्ला समूह' के स्वामित्व में हैं, इसे समझने के लिए, इन कंपनियों की शेयरधारिता का निम्नलिखित विश्लेषण पर्याप्त होना चाहिए:

(1) जसवंत शुगर मिल्स लिमिटेड	
2,00,000 शेयर	
(i) जसवंत स्ट्रॉ बोर्ड लिमिटेड	44,845
(ii) नेशनल फाइनेंस लिमिटेड	67,390
(iii) राष्ट्रीय निर्माण	
और विकास निगम लिमिटेड	<u>47,800</u>
	1,60,035
	(यानि 80 प्रतिशत से अधिक)
(2) जसवंत स्ट्रॉ बोर्ड लिमिटेड	
6,176 शेयर।	
(i) नेशनल फाइनेंस लिमिटेड	4,783
(ii) राष्ट्रीय निर्माण	
एवं विकास निगम लिमिटेड	<u>500</u>

5,200 विषम

(या लगभग 84 प्रतिशत)

872

SUPREME COURT REPORTS

[1962] SUPP.

(3) नेशनल फाइनेंस लिमिटेड (निर्धारिती  
कंपनी) 50,000 शेयर।

गणेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

48,000

(या 96 प्रतिशत से अधिक)

(4) नेशनल कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट

कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1,30,504 शेयर.

1,30,500

गणेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(लगभग सभी)

(5) गणेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन

लिमिटेड 50,000 शेयर।

49,795

रघुनाथ इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड (पूंजी का 99.6 प्रतिशत)

(6) रघुनाथ इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड

10,000 शेयर।

(i) श्री योध राज भल्ला

1,500

(ii) श्रीमती भल्ला

1,000

(iii) श्री एन. सी. मल्होत्रा

(जीजाजी)

1,000

(iv) श्री राम प्रसाद (ससुर)

1,000

(v) श्री दीना नाथ (सचिव)

1,000

(vi) नेशनल फाइनेंस लिमिटेड

3,499

(vii) श्री पियारे लाल सह

1

9,000

(90 प्रतिशत).

परिणामी स्थिति इस प्रकार बताई जा सकती है: गणेश फिनासे कॉर्पोरेशन लिमिटेड व्यावहारिक रूप से एस्सेरेड कंपनी और नेशनल कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मालिक है, रघुनाथ

इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड व्यावहारिक रूप से गणेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मालिक है, और योध राज भल्ला समूह व्यावहारिक रूप से मालिक है। रघुनाथ इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड के मालिक हैं।

जसवन्त शुगर मिल्स लिमिटेड का व्यावहारिक स्वामित्व जसवन्त स्ट्रॉ बोर्ड लिमिटेड, नेशनल फाइनेंस लिमिटेड और नेशनल कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास है, और जसवन्त स्ट्रॉ बोर्ड लिमिटेड का व्यावहारिक स्वामित्व नेशनल फाइनेंस लिमिटेड और नेशनल कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पास है। इस प्रकार, पूरे समूह का स्वामित्व एक के पास है, और इसमें कोई संदेह नहीं है।

मधुसूदन मिल्स लिमिटेड के शेयर निम्नलिखित परिस्थितियों में हासिल किए गए थे: जुलाई 1948 में, श्री योध राज भल्ला, जो इन छह कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी के कारण निदेशक मंडल के निर्णयों को प्रभावित करने की स्थिति में थे मेसर्स भदानी ब्रदर्स लिमिटेड से मिल्स के 26,547 शेयर खरीदने की व्यवस्था की, जो मिल्स के प्रबंध एजेंट थे। शेयरों का यह ब्लॉक मिलों की कुल जारी पूंजी का लगभग 80 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करता है। खरीद 400 रुपये प्रति शेयर पर की गई थी जब बाजार में कीमत लगभग रु. 250 प्रति शेयर थी। बाजार से शेष शेयरों में से 200 शेयर 252-8-0 प्रति शेयर रुपये पर खरीदे गए थे जो तब उद्धृत मूल्य था। अब, ये शेयर जसवंत शुगर मिल्स लिमिटेड द्वारा खरीदे गए थे, लेकिन शेयरों की खरीद के लिए पैसा कुछ अन्य कंपनियों से उधार लेकर प्राप्त किया गया था। जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, ये कंपनियाँ पूरी तरह से 'योध राज भल्ला समूह' के नियंत्रण में थीं। धन की व्यवस्था इस प्रकार थी:

रु 14,75,000 – निर्धारिती कंपनी से उधार लिया

रु 5,00,000 – राष्ट्रीय निर्माण एवं विकास निगम लिमिटेड से

रु 55,00,000 – निर्धारिती कंपनी से लेकिन गणेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अग्रिम

शेयर निम्नानुसार पंजीकृत किए गए थे:

10,500	शेयर निर्धारिती कंपनी के नाम पर पंजीकृत थे।
5,400	शेयर नेशनल कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम पर , और शेष राशि जसवन्त शुगर मिल्स लिमिटेड के नामांकित व्यक्तियों के नाम पर, जिसका मतलब, बड़े पैमाने पर, 'योध राज भल्ला ग्रुप' से संबंधित व्यक्ति थे।

9 अक्टूबर, 1949 को, निर्धारिती कंपनी ने 400 प्रति शेयर रुपये में 15,547 शेयर जसवंत शुगर मिल्स लिमिटेड से खरीदे और निर्धारिती कंपनी द्वारा भुगतान की गई राशि को खरीद मूल्य में समायोजित किया गया और शेष राशि का भुगतान किया गया। उसी दिन, शेष 11,000 शेयर जसवन्त शुगर मिल्स लिमिटेड द्वारा नेशनल कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 400 प्रति शेयर रुपये में बेच दिए गए। इस प्रकार, उस तारीख को जसवंत शुगर मिल्स लिमिटेड का वर्तमान मामले से कोई संबंध नहीं रह गया। यह बताया जा सकता है कि जिस तारीख को दोनों लेनदेन हुए, बाजार में 217-8-0 रुपये कीमत लगभग थी। जसवंत शुगर मिल्स लिमिटेड के शेयरों से अलग होने से पहले, उन्होंने मधुसूदन मिल्स लिमिटेड के नए निदेशक मंडल की नियुक्ति की थी, और ये नए निदेशक भी उसी समूह के थे। मेसर्स भदानी ब्रदर्स लिमिटेड की प्रबंध एजेंसी को समाप्त कर दिया गया था, और उसी दिन जिस दिन इन प्रबंध एजेंटों से शेयर खरीदे गए थे, निर्धारिती कंपनी को मिल्स के क्रय और बिक्री एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया था। निर्धारिती कंपनी ने क्रय और विक्रय एजेंट के रूप में लाभांश और कमीशन के माध्यम से इन शेयरों के अधिग्रहण से भारी लाभ कमाया। हालाँकि, अक्टूबर और नवंबर, 1948 में उन्होंने डालमिया सीमेंट एंड मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड को 6,525 शेयर 400 प्रति शेयर रुपये में बेच दिए। ये शेयर बाद में उसी समूह में वापस आ गए;

लेकिन यह ऐसा मामला नहीं है जिससे हम तुरंत चिंतित हों।

7 अप्रैल, 1949 को, निर्धारिती कंपनी द्वारा नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड को 4,500 शेयर प्रति शेयर 181 रुपये में बेचे गए थे परिणामस्वरूप 8,80,000/- रुपये का नुकसान हुआ। 8,80,000, और 1 जून 1949 को 3,000 शेयरों का एक और ब्लॉक नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड को प्रति शेयर 180 रुपये में बेच दिया गया 5,86,312/- रुपये का नुकसान हुआ। हम पहली बिक्री से होने वाले नुकसान से चिंतित नहीं हैं, जिस पर आकलन वर्ष, 1950-51 में विचार किया गया था, और जिसके संबंध में पंजाब उच्च न्यायालय में एक संदर्भ लंबित है। हम आकलन वर्ष, 1951-52 से संबंधित दूसरे वर्ष में हुए नुकसान से चिंतित हैं। उस वर्ष, शेयरों की बिक्री पर होने वाले नुकसान को किए गए मुनाफे से समायोजित करने की मांग की गई थी, और नुकसान ने व्यावहारिक रूप से मुनाफे को रद्द कर दिया था। निर्धारिती कंपनी द्वारा दो अवसरों पर बेचे गए शेयर अमृत भूषण (श्री योध राज भल्ला के रिश्तेदार) को बेचे गए, जिन्होंने उसी दिन मेसर्स नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड को 8 औनास प्रति शेयर के मामूली लाभ पर बेच दिया जो दलाली थी। इस प्रकार, शुरुआत और अंत में, हालांकि कई लेनदेन हुए, शेयर 'योध राज भल्ला समूह' की संपत्ति बने रहे। सवाल यह है कि क्या शेयरों की बिक्री पर होने वाले नुकसान को उस वर्ष के मुनाफे से समायोजित किया जाएगा जिसमें बिक्री और मुनाफा क्रमशः कमाया गया था।

निर्धारिती कंपनी का निर्धारण आयकर अधिकारी, मेरठ द्वारा निर्धारण वर्ष, 1951-52 के लिए किया गया था। उस वर्ष के मूल्यांकन में, मधुसूदानी मिल्स लिमिटेड के 4,520 शेयरों की बिक्री से 8,78,062-8-0.रुपये की हानि को निर्धारिती कंपनी के मुनाफे से समायोजित किया गया था। निर्धारण वर्ष, 1951-52 के लिए निर्धारिती कंपनी के मामले पर आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्कल V, नई दिल्ली द्वारा विचार किया गया था, जिन्हें उपरोक्त अन्य कंपनियों के मामले भी स्थानांतरित कर दिए गए थे।

इन कंपनियों के मामलों पर गौर करके, उन्हें पता चला कि मधुसूदन मिल्स लिमिटेड के शेयर 'योध राज भल्ला समूह' द्वारा ऐसी कीमत पर खरीदे गए थे, जो वर्तमान बाजार मूल्य से लगभग दोगुना था और asse-ssce कंपनी को समान कीमत पर स्थानांतरित कर दिए गए थे। उन्होंने पाया कि यह मेसर्स भदानी ब्रदर्स लिमिटेड को उनकी प्रबंध एजेंसी से हटाने और निर्धारिती कंपनी के लिए मिल्स की खरीद और बिक्री एजेंसी को सुरक्षित करने के उद्देश्य से किया गया था। मेसर्स भदानी ब्रदर्स लिमिटेड से खरीद की तारीख पर, जसवंत शुगर मिल्स लिमिटेड ने अपने नियंत्रित हित को देखते हुए इस उद्देश्य को हासिल किया। भदानी ब्रदर्स, लिमिटेड उस तारीख से प्रबंध एजेंट नहीं रहे, और मधुसूदन मिल्स लिमिटेड की क्रय और विक्रय एजेंसी निर्धारिती कंपनी को दे दी गई, हालांकि उस दिन उसने ऋण देने के अलावा और कुछ नहीं किया था। मूल्यांकन वर्ष, 1951-52 में, 3,000 शेयरों की बिक्री पर 5,86,312-8-0 रुपये की हानि हुई, इसलिए इसे पूंजीगत हानि मानकर अस्वीकार कर दिया गया। अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा अपील पर आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्कल V, नई दिल्ली के आदेश की पुष्टि की गई। निर्धारिती कंपनी द्वारा आगे की अपील पर, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, दिल्ली ने अपीलीय सहायक आयुक्त के आदेश को उलट दिया, और माना कि हानि एक व्यापारिक हानि थी।

चाहे कोई विशेष हानि व्यापारिक हानि हो या पूंजी पक्ष की हानि, निस्संदेह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। लेकिन यह बार-बार माना गया है कि प्रश्न शुद्ध तथ्य का नहीं है, और इसमें हमेशा तथ्य और कानून का मिश्रित प्रश्न शामिल होता है। वर्तमान में हम जिन मामलों का संदर्भ देंगे, उनमें यह प्रस्ताव रखा गया है, और उन मामलों में यह भी संकेत दिया गया है कि मामले को तथ्यों के संदर्भ में कैसे देखा जाना चाहिए। आयकर आयुक्त बनाम रामनारायण संस लिमिटेड <sup>(1)</sup> में, कंपनी शेयरों की डीलर थी और अन्य

कंपनियों की प्रबंध एजेंसियों का अधिग्रहण करने का व्यवसाय भी चलाया। कंपनी ने मेसर्स ससून जे. डेविड एंड कंपनी लिमिटेड से एक कपड़ा मिल की प्रबंध एजेंसी का अधिग्रहण किया, और उसी लेनदेन के हिस्से के रूप में मिल्स के 2,507 शेयर खरीदने पर भी सहमति व्यक्त की। 1,507 शेयर 2,321-8-0 प्रति शेयर रुपये पर खरीदे गए और शेष 1,000 शेयर 1,500 प्रति शेयर रुपये पर खरीदे गए। बाज़ार में ये शेयर 1,610 रु. पर बोले गए बाद में, 4,000 शेयर 1,78,000 रुपये के नुकसान पर बेचे गए। इसे कंपनी की पुस्तकों में व्यावसायिक घाटे के रूप में दिखाया गया था, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया था, क्योंकि शेयरों को शेयर डीलरों के रूप में कंपनी के व्यवसाय के स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में नहीं रखा गया था। बॉम्बे उच्च न्यायालय के संदर्भ में, एक डिविजनल बेंच ने ट्रिब्यूनल के दृष्टिकोण को बरकरार रखा। छागला, सी. जे. ने अदालत का फैसला सुनाते हुए कहा कि एक प्रबंध एजेंसी एक स्थायी प्रकृति की संपत्ति है, मामले को देखने का तरीका यह जांचना है कि शेयर हासिल करने का प्राथमिक इरादा क्या था। तब विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने किशन प्रसाद एंड कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त (1) मामले में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया, जहां यह देखा गया था:

"ऐसा लगता है कि शेयर खरीदने में निर्धारित कंपनी का उद्देश्य पूरी तरह से तीसरी मिल की प्रबंध एजेंसी प्राप्त करना था, जो निस्संदेह एक स्थायी प्रकृति की संपत्ति होती और उन्हें मुनाफा दिलाती लेकिन शुरुआत से ही ऐसा था निर्धारित कंपनी की ओर से शेयरों को लाभ पर दोबारा बेचने या अन्यथा उनमें सौदा करने का कोई इरादा नहीं है।"

विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने तब इस तर्क पर विचार किया कि शेयरों का एक ब्लॉक, यदि खरीदा भी जाए, तो अधिक कीमत पर खरीदना पड़ सकता है, और इस प्रकार देखा गया:

"शेयरों का एक व्यापारी बाजार मूल्य से कम कीमत पर बड़ी संख्या में शेयर प्राप्त करने में सफल हो सकता है यदि विक्रेता कठिनाइयों में है और अपने शेयरों से छुटकारा पाना चाहता है और तरल संपत्ति

प्राप्त करना चाहता है। लेकिन हमने यह नहीं सुना है कि किसी शेयर विक्रेता ने बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर बड़ी संख्या में शेयर खरीदे हों। दूसरी परिस्थिति जो इस मामले में समान रूप से मजबूत है, वह यह है कि शेयर प्रबंध एजेंसी के अधिग्रहण के लिए खरीदे गए थे। इसलिए निर्धारिती कंपनी का वास्तविक उद्देश्य इन शेयरों में व्यापार करना नहीं था, इन शेयरों से लाभ कमाना नहीं था, बल्कि एक पूंजीगत संपत्ति हासिल करना था जिससे वह प्रबंध एजेंसी कमीशन कमा सके और लाभ कमा सके।"

मेसर्स रामनारायण एंड संस लिमिटेड ने फिर इस न्यायालय में अपील की, और बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा गया। इस न्यायालय का निर्णय रामनारायण संस (प्रा.) लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त <sup>(1)</sup> मामले में बताया गया है। इस न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि इस बात पर विचार करते समय कि कोई लेनदेन व्यापार की प्रकृति में एक साहसिक कार्य था या नहीं, इसकी जांच करदाता के आशय के आलोक में, "व्यापार या व्यवसाय की अवधारणा से जुड़ी कानूनी आवश्यकताओं" को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। बाजार मूल्य से ऊपर की कीमत जो उस मामले में भुगतान किया गया था को देखते समय विचार किया गया कि:

"यह मानते हुए भी कि अपीलकर्ताओं ने मेसर्स ससून जे. डेविड एंड कंपनी लिमिटेड से 2,507 शेयरों का पूरा ब्लॉक हासिल कर लिया है – शेयर निदेशकों के नाम पर स्थानांतरित कर दिए हैं, जो उनके पास केवल अपीलकर्ताओं के नामांकित व्यक्ति के रूप में हैं – प्रति शेयर कीमत प्रचलित बाजार दर से काफी अधिक थी। लेनदेन में प्रवेश करने का एकमात्र कारण, जिसे अन्यथा विवेकपूर्ण व्यवसाय के रूप में लेनदेन नहीं माना जा सकता था, एक प्रबंध एजेंसी का अधिग्रहण था। यदि मौजूदा बाजार मूल्य से दस लाख रुपये अधिक कीमत पर शेयरों के एक बड़े ब्लॉक के

अधिग्रहण का उद्देश्य प्रबंध एजेंसी का अधिग्रहण था, तो यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि शेयरों को खरीदने का इरादा उन्हें हासिल करने का नहीं था। शेयरों में अपीलकर्ताओं के व्यापार का हिस्सा।"

उपरोक्त दो निर्णय केवल लंबे समय से चले आ रहे सिद्धांत का अनुप्रयोग हैं, जिसे अतीत में बार-बार कहा गया है। *ओरिएंटल इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त* <sup>(1)</sup> में, उस सिद्धांत को दोहराया गया था, और जिस उद्देश्य के लिए कंपनी का गठन किया गया था, यह था कि उसने शेयरों में व्यापार की विशेषताओं के साथ सौदे में निवेश नहीं किया था, लेकिन किसी विशेष उद्यम के वास्तविक उद्देश्य का पता लगाने के लिए उस तथ्य के साथ-साथ अन्य परिस्थितियों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

इससे पहले कि हम वर्तमान मामले पर विचार करें, इस न्यायालय के एक अन्य मामले पर ध्यान दिया जा सकता है। *राजपूताना टेक्सटाइल्स बनाम आयकर आयुक्त* <sup>(2)</sup> मामले में विपरीत निष्कर्ष पर पहुंचा गया था। वहां, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर, यह माना गया कि शेयरों में एक विशेष सौदा एक वाणिज्यिक उद्यम था और इसमें व्यापार की प्रकृति में एक साहसिक कार्य के सभी गुण थे। उस स्थिति में, लेन-देन एक मंदी भुगतान के साथ एकल या अविभाजित था, क्योंकि प्रबंध एजेंसी के लिए अलग से 12,50,000 रुपये और शेयरों के लिए 83,98,000 रुपये का भुगतान किया गया। दोनों अधिग्रहण अलग-अलग होने के कारण, शेयरों की बिक्री पर लाभ को राजस्व पक्ष पर लाभ माना गया।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि मधुसूदन मिल्स लिमिटेड के शेयर बाजार मूल्य से काफी अधिक कीमत पर हासिल किए गए थे। वास्तव में, भुगतान की गई कीमत लगभग दोगुनी थी। व्यापारिक दृष्टिकोण से ऐसा सौदा विवेकपूर्ण नहीं था, जब तक कि खरीदार को कुछ लाभ का अन्य रास्ता न हो। हमारे सामने यह

तर्क दिया गया कि यह इस उम्मीद में एक सट्टेबाजी का सौदा था कि जब कपड़ा उद्योग पुनर्जीवित होगा तो शेयरों की कीमत मजबूत होगी। यदि यह इरादा था, तो संभवतः यह तर्क दिया जा सकता है कि खरीदारों ने अपनी गणना में गलती की, और एक व्यापारिक लेनदेन में नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन, क्या जसवन्त शुगर मिल्स लिमिटेड के निदेशकों की यही मंशा थी? जिन लोगों ने शेयर बेचे, उनके पास न केवल शेयरों का बल्कि मधुसूदन मिल्स लिमिटेड की प्रबंध एजेंसी का भी कब्जा था, और जसवंत शुगर मिल्स लिमिटेड के निदेशकों का इरादा विक्रेताओं को प्रबंध के पद से हटाना था और ऐसी एजेंटों या अन्य एजेंसियों का पूरा लाभ अपने लिए प्राप्त करना। निर्धारिती कंपनी ने आग्रह किया है कि हो सकता है कि यह इरादा जसवन्त शुगर मिल्स लिमिटेड का रहा हो, लेकिन करदाता कंपनी का नहीं, जिसने उस दिन, केवल जसवन्त शुगर मिल्स लिमिटेड को ऋण दिया था। हालांकि, दिलचस्प बात यह है कि तत्काल लाभ सौदे का हिस्सा मिलों की बिक्री और खरीद एजेंसी का अधिग्रहण था, और यह जसवंत शुगर मिल्स लिमिटेड के पक्ष में नहीं बल्कि निर्धारिती कंपनी के पक्ष में प्राप्त किया गया था, भले ही 15 जुलाई, 1948 (खरीद की तारीख) को निर्धारिती कंपनी ने सिक्वोरिटी के जरिए 10,500 शेयरों का रजिस्ट्रेशन अपने नाम पर हासिल कर लिया था। इस तरह से निर्धारिती कंपनी का पक्ष क्यों लिया गया, इसकी तलाश करना ज्यादा दूर की बात नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या जसवन्त शुगर मिल्स लि. उस एजेंसी या निर्धारिती कंपनी का अधिग्रहण किया; इसका लाभ व्यक्तियों के एक ही समूह को मिला। शेयरों की बिक्री का लेनदेन भी उनकी खरीद के तीन महीने के भीतर किया गया था, और निर्धारिती कंपनी ने न केवल 10,500 शेयर खरीदे, जो उसके नाम पर थे, बल्कि 15,547 शेयर भी खरीदे, जिससे करदाता कंपनी को मिल्स के मामलों में एक नियंत्रित आवाज मिल गई।

निर्धारिती कंपनी ने बिक्री और क्रय एजेंसी को बरकरार रखा, जो बहुत लाभदायक थी। दरअसल, पहले साल में इसके निवेश पर रु. 14 लाख के विषम लगभग 7 लाख रुपये का मुनाफा कमाया।

इसलिए, सवाल यह होगा कि क्या शेयरों को खरीदने में निर्धारिती कंपनी केवल स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में शेयरों का सौदा करना चाहती थी, या एक स्थायी प्रकृति की पूंजीगत संपत्ति प्राप्त कर रही थी। यह प्रश्न तथ्यात्मक, शुद्ध और सरल नहीं है, बल्कि मामले की सिद्ध परिस्थितियों से कानून में एक अनुमान का है।

आयकर अधिकारी ने निर्धारिती कंपनी के खिलाफ इस सवाल का फैसला करते समय, कई परिस्थितियों की ओर इशारा किया, जिससे स्पष्ट रूप से पता चला कि यह एक सट्टेबाज द्वारा शेयरों के रूप में शेयरों की खरीद मात्र नहीं थी, जो एक बड़ा ब्लॉक खरीदकर, कभी-कभी थोड़ा बाजार दर से भी ज्यादा भुगतान करता है। भदानी ब्रदर्स लिमिटेड के पास न केवल शेयर बल्कि प्रबंध एजेंसी का भी स्वामित्व था, और यह स्पष्ट है कि वे प्रबंध एजेंसी के लिए शुल्क लिए बिना शेयर नहीं छोड़ेंगे। 400 रुपये प्रति शेयर की कीमत बाजार मूल्य के अनुपात से इतना अधिक था कि यह, अपने आप में, मात्र शेयरों से कुछ अधिक के अधिग्रहण का संकेत देता था। आयकर अधिकारी के अनुसार, वास्तविक इरादा मिलों की आकर्षक एजेंसियों का अधिग्रहण करना था, और यह इरादा, चाहे वह जसवंत शुगर मिल्स लिमिटेड या मूल्यांकन कंपनी या दोनों के पास था, व्यक्तियों के एक ही समूह का था। अपीलीय सहायक आयुक्त ने आयकर अधिकारी के विचार का समर्थन किया; लेकिन ट्रिब्यूनल ने एक कंपनी और दूसरी कंपनी के बीच अंतर किया है, और वह अंतर निर्धारिती कंपनी द्वारा हम पर थोपा गया है। *सॉलोमन बनाम सॉलोमन एंड कंपनी लिमिटेड* <sup>(1)</sup> के प्रसिद्ध मामले पर भरोसा करते हुए, हमारे सामने यह तर्क दिया गया था कि प्रत्येक कंपनी को एक अलग इकाई के रूप में देखा जाना चाहिए, और किसी अन्य कंपनी के लिए, भले ही कंपनियों का स्वामित्व समान हो किसी एक कंपनी के इरादे को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। कंपनी को प्रभावित करने वाले प्रस्ताव के रूप में इसे गलत नहीं कहा जा सकता; लेकिन हम निर्धारिती कंपनी के एक अलग कानूनी इकाई होने के सैद्धांतिक प्रश्न से चिंतित नहीं हैं, बल्कि प्रश्न यह है कि क्या निर्धारिती कंपनी द्वारा किया गया कोई विशेष

नुकसान पूंजी या राजस्व हानि है। दो कंपनियाँ, अर्थात् जसवन्त शुगर मिल्स लिमिटेड और निर्धारिती कंपनी को व्यक्तियों के एक ही समूह द्वारा निर्देशित किया गया था, और तथ्य बताते हैं कि भले ही जसवन्त शुगर मिल्स लिमिटेड ने अस्थायी रूप से शेयरों का अधिग्रहण किया, लेकिन उन्होंने अधिग्रहण के सभी लाभ निर्धारिती को प्रदान किए। पहले दिन से ही निर्धारिती कंपनी भी अंततः एक अन्य कंपनी के साथ सभी शेयरों के कब्जे में आ गई, जिसका निर्देशन भी उन्हीं व्यक्तियों द्वारा किया गया था, और जसवंत शुगर मिल्स लिमिटेड तीन महीने के भीतर तस्वीर से बाहर हो गई। इन परिस्थितियों में, यह देखना आसान है कि जसवंत शुगर मिल्स लिमिटेड का हस्तक्षेप केवल अंग्रेजी मामले के लाभ को सुरक्षित करने के लिए एक उपकरण था, जिसका हमने उल्लेख किया है। ऐसा कभी इरादा नहीं था कि जसवन्त शुगर मिल्स लिमिटेड शेयरों को अपने पास रखेगी या शेयरों के एक ब्लॉक के अधिग्रहण से होने वाले लाभ को अपने पास रखेगी, जिससे धारक को मधुसूदन मिल्स लिमिटेड के मामलों में एक निर्णायक आवाज मिल सके। योध राज भल्ला समूह' निर्धारिती कंपनी के लाभ के लिए था, और यह एक स्थायी प्रकृति के हित का अधिग्रहण था।

इस संबंध में, डालमिया सीमेंट एंड मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड के साथ लेनदेन का संदर्भ दिया गया था, जिसमें डालमिया सीमेंट एंड मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड ने समान कीमत अर्थात् 400 रु. प्रति शेयर का भुगतान किया था। शायद, डालमिया कंपनी अपने तरीके से हितों को नियंत्रित करने के पीछे थी, और यह ध्यान देने योग्य बात है कि थोड़े समय के भीतर, उन शेयरों को फिर से वही समूह मिल गया। इसी तरह, इस समूह में शेयरों भी अन्य के हाथ में गए अमृत भूषण की एजेंसी के माध्यम से हैं, जो निस्संदेह एक दलाल है, लेकिन श्री योध राज भल्ला का रिश्तेदार भी है, जो प्रति शेयर केवल 8 आने की सीमा तक मुनाफा कमाता था, और उसी दिन एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शेयर खरीदता और बेचता था। यह सब दर्शाता है कि इन कंपनियों के मामले केंद्रीय रूप से व्यवस्थित थे, और यह इरादा था कि शेयरों के एक बड़े ब्लॉक को बाजार

में प्राप्त करने की तुलना में बहुत अधिक कीमत पर अधिग्रहण करके निर्धारिती कंपनी को लाभ पहुंचाया जाए, ताकि लाभदायक चरित्र की कुछ एजेंसियों का अधिग्रहण किया जा सके।

हमारी राय में, इस लेनदेन को पूंजी पक्ष में एक माना जाना चाहिए। शेयरों को कभी भी स्टॉक-इन-ट्रेड का हिस्सा नहीं माना गया। उन्हें बाज़ार में नहीं बेचा गया था, बल्कि उसी समूह से संबंधित किसी अन्य कंपनी को घाटे में बेचा गया था, जिसका स्पष्ट उद्देश्य लाभ के विरुद्ध घाटे की भरपाई करना था, इस प्रकार लाभ को रद्द करना और उन्हें कराधान से बचाना था।

परिणामस्वरूप, प्रतिवादी पर लागत सहित अपील की अनुमति दी जाती है।

अपील स्वीकृत ।

(1) [1962] 2 एस.सी.आर. 276

(2) [1960] 40 आई.टी.आर. 605.

(1) [1962] 2 एस.सी.आर. 276

(2) सी. ए. क्रमांक 176 का 1959, निर्णय दिनांक अप्रैल 24, 1961

(3) [1962] 2 एस.सी.आर. 839

(4) [1962] 1 एस.सी.आर. 941

(5) [1960] 1 आई.टी.आर 605

(1) [1960] 1 आई.टी.आर 605

(1) [1960] 31 आई.टी.आर 17

(1) [1961] 2 एस.सी.आर. 904

(1) [1958] एस.सी.आर. 49

(2) [1961] 42 आई.टी.आर 743

(1) [1897] ए. सी. 22

**Translated , Validated & Corrected by**

**SMT. NEHA YATI MISHRA**

II ADDL. JUDGE TO THE COURT OF I CIVIL JUDGE CLASS-I RAIPUR





